

विचार बिन्दु

धन उत्तम कर्मों से उत्पन्न होता है, प्रगल्भता (साहस, योग्यता व दृढ़ निश्चय) से बढ़ता है, चतुराई से फलता फूलता है और संयम से सुरक्षित होता है।

—विदुर

राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट: एक गंभीर सामाजिक चुनौती

राजस्थान की पहचान अपने समृद्ध सांस्कृतिक वैभव, पारंपरिक स्वाद और विशिष्ट खानपान के लिए जानी जाती है। यहाँ का ‘दाल-बाटी-चूरमा’, ‘धेवर’, ‘प्याज कचौरी’ और ‘भिचौ बड़ा’ न केवल स्थानीय जीवन का हिस्सा है बल्कि राजस्थान की आतिथ्य संस्कृति का प्रतीक भी है। मगर दुख की बात है कि जिन खाद्य परंपराओं पर प्रदेश को गर्व रहा है, आज वे ही मिलावट की मार झेल रही हैं। खुले बाजारों और त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट अब सामान्य सी बात हो गई है, जो न केवल उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह समाज के नैतिक ढाँचे को भी कमजोर करती है।

मिलावट केवल दूध, घी या मसालों तक सीमित नहीं रही। आज यह खाद्य श्रृंखला के लगभग हर हिस्से में प्रवेश कर चुकी है। दूध में सिंथेटिक पदार्थ, मिठाइयों में कृत्रिम रंग और एसेंस, दालों में पत्थर और पॉलिशिंग के रसायन, तेल में खतरनाक औद्योगिक मिश्रण और मसालों में अशुद्ध रासायनिक तत्व मिलाए जा रहे हैं। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक छिपी हुई महामारी के समान है – जो धीरे-धीरे हर आयु वर्ग को प्रभावित कर रही है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से लेकर जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरी केंद्रों तक, बाजारों में मिलावटी खाद्य सामग्री की उपलब्धता आम नागरिक के स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार कर रही है।

मिलावट के पीछे कई कारक कार्यरत हैं। सबसे प्रमुख कारण है व्यापारिक लाभ की लालसा। सस्ता माल दिखाकर अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति अनेक छोटे-बड़े व्यापारियों में गहरी जड़ें जमा चुकी है। दूसरा बड़ा कारण है निगरानी और प्रवर्तन की सीमित क्षमता। राज्य सरकार के पास खाद्य निरीक्षकों की संख्या अभी भी इतनी नहीं है कि वह हर जिले व हर मंडी स्तर पर कठोर निगरानी रख सके। तीसरी वजह है आम नागरिक का जागरूक न होना। बहुत बार उपभोक्ता केवल कीमत देखकर वस्तु खरीद लेता है, गुणवत्ता की जांच पर ध्यान नहीं देता। यह उपभोक्ताओं की असावधानी उन मिलावटखोरों को बढ़ावा देती है, जो जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में संकोच नहीं करते।

त्योहारी सीजन में तो स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है। दीपावली, होली, तीज, गणगौर जैसे अवसरों पर जब मिठाई और नमकीन की खपत कई गुना बढ़ जाती है, तो मुनाफाखोर तत्व नकली दूध, सिंथेटिक मावा और रासायनिक रंगों का प्रयोग करके हजारों टन मिठाइयों बाजार में उतारते हैं। स्वास्थ्य विभाग अक्सर ऐसी सामग्रियों के सैंपल तो लेता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की जटिलता और न्यायिक देरी के कारण अपराधियों पर कठोर दंड नहीं हो पाता। यही ढीलवाइ इस अपराध को स्थायी रूप से समाप्त होने से रोकती है।

राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। ‘राजस्थान राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन’ समय-समय पर अभियान चलाकर नमूने एकत्र करता है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

मिलावट नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी, और प्रशासन – तीनों की सहभागिता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सावधान रहना चाहिए। पैकड वस्तुओं की कार्रवाई करता है। ‘मिशन मिलावट मुक्त राजस्थान’ के अंतर्गत हाल के वर्षों में अनेक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में नकली घी एवं मावा बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ जैसी मोबाइल यूनिटें भी शुरू की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच करती हैं। इन पहलों से कुछ सुधार हुआ है, परंतु समस्या की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

कभी-कभी, कितने असहाय से लगते हैं देश के शासक, रहनुमा लोग----



महावीर सिंह

रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया,

इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो

— दुर्धंत कुमार

अभी-अभी 9 दिसंबर को त्रिपुरा के एक नौजवान होनहार छात्र एंजेल चकमा की, उत्तराखंड में की गई नृशंस हत्या पर किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री में कुछ इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की ---- ऐसी घटनाएं चाहे कहीं भी हो वे निंदनीय है और सब को मिल कर उनकी निंदा करनी चाहिए। इसे एक समाचार मात्र नहीं मानना चाहिए। बहुत से ऐसे जिन्हें बोलना चाहिए था, सदा की तरह खामोश रहे।

सुनिए मंत्री जी ---- 10 दिसंबर को शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं, 12 दिसंबर को हल्की सी, जानलेवा हमले वाली एफआईआर दर्ज हुई, हत्या की धारा तो जुड़ी 26 दिसंबर को, उस की मृत्यु के बाद --- और सुनें मंत्री जी ---- उसे चाहनी, मोमोजन जैसी नस्लीय गालियां दी गई।

लगता है, प्राध्वं में यह सब आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सत्य से परे लगा होगा या सत्य से वाकिए होते हुए भी आंखे मूंदे रखी होंगी क्योंकि सत्ता के लिए सत्य से मुंह भी फेर लिया जाता है किंतु सत्ता से परे भी सत्य होता है, जो लाख प्रयासों के

बावजूद छुपता नहीं।

क्या कोई आमदमी इस पर विश्वास करेगा कि आप दोनों को और अन्य समस्त बड़े-बड़े सत्तासीन रहनुमाओं को 20 दिन से अधिक का समय लगा यह जानने में की नस्लीय आधार पर एक होनहार युवक को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई? वह भी उतर पूर्व के एक बेहद संवेदनशील राज्य के युवक की।

सत्तासीन रहनुमाओं, कोई भी देशप्रेमी भारतीय नागरिक आप रहनुमाओं के आंसुओं वाली (असली थी या – नकली थी, भगवान जाने!!!)

भावनाओं से सहमत होगा किंतु ---- यह कोई इकलौती घटना भी तो नहीं--

भारत दुनिया भर में फैले हिंदुओं की चिंता करता है। किसी भी दूसरे देश में हिंदुओं की हत्या, नस्लीय दुर्व्यवहार, पर भारत कड़ा विरोध करता है। यह सब हमारे यहां की प्रेस, मीडिया जनता को समझाता रहता है, सरकार राष्ट्रवादी है! देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मांब लिंगिंच पर सत्ताा कयों पसरा था? क्या देश के नागरिकों की देश में ही गौ रक्षा, जाति-धर्म के आधार पर निजी या कई संगठनों के आपराधिक गिरोहों द्वारा सार्वजनिक रूप से हत्याओं पर चुप्पी राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है ???

और सुने ---- अभी अभी गाजियाबाद में, हिंदू रक्षक सेना ने घर-घर जाकर तलवार फरसे बांटे हैं ---- - कहा बताया, यदि किसी ओर देश जैसी स्थिति यहां आए तो उन--- काट दो ---- क्या किसी अखबार, मीडिया में प्रमुखता से पढ़ने-सुनने को मिला!!!!

100 प्रतिशत सत्य,बंगला देश में कई हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई है। धार्मिक उन्माद से किसी की भी हत्या होती है वह भर्त्सनीय है। ऐसी हत्या भारत में हो, बंगला देश में हो या किसी भी अन्य देश में हो उसकी हर व्यक्ति द्वारा कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

देश के विभिन्न हिस्सों में

फसल कटाई से इनकार पर पेशाब पिलाया गया। चुरू में पुरानी रंजिश के एक दलित व्यक्ति को अपहरण कर पेशाब पिलाया गया। मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया। अजमेर नाबालिग दलित लड़के को शराब और पेशाब पिलाया। भिंड में एक दलित ड्राइवर को नौकरी छोड़ने पर पेशाब पिलाया गया। 2025 में लखनऊ में 65 वर्षीय दलित बुजुर्ग का मंदिर के पास में पेशाब लीक हुआ तो उस से पेशाब चटवाया गया। 2019 में थिबियम, पेनागराम (तमिलनाडु) में दलितों को मल खिलाया और पेशाब पिलाया गया। 2023, मध्य प्रदेश में दो युवकों को चेहरे काले कर मल खिलाया गया। केरल में एक दलित कॉलोनी के पानी में मल मिलाने की घटना हुई। 2025, मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेता पर दो व्यक्तियों को जबरन मल खिलाने का आरोप लगा। टट्टी खिलाने की अत्यंत अपमानजनक घटनाएं अक्सर जातिगत उत्पीड़न से जुड़ी।

इस प्रकार के मामलों की जानकारीयें एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट्स, गूगल अथवा गोर पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। भारत के किसी भी धर्म के कट्टरपंथी अगर ऐसा करते हैं तो हर धर्म के व्यक्ति द्वारा इसकी कड़ी से कड़ी आलोचना करनी चाहिए। ऐसे मामलों में हिंदू मुसलमान कदापि नहीं होना चाहिए।

अब जरा विचार करें --- भारत में कई बड़े-बड़े सामाजिक सुधार ,सामाजिक समरसता लाने की बात करने वाले, जातिगत भेद मिटा ने की ताल ठोकने वाले संगठनों में कुछ किया?? कभी सुना इन सब ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, जातिगत पूर्वग्रह समाप्त करने के लिए कोई सार्थक आंदोलन किए हैं?? कई बार तो आम नागरिक यह महसूस करने लगता है कि क्या ऐसे उत्पत्ति लोग यह मान कर चक्ते है कि इनके तिर पर सत्ता की छत्र छाया है।

विराटनगर : मैड कस्बे के खटीकों के मोहल्ले में दस वर्ष से पेयजल संकट

घरों में जलदाय विभाग के कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं आता, जबकि विभाग द्वारा हर महीने पानी का बिल भेजा जा रहा है

— दुर्धंत कुमार

पावटा, (निर्स)।विराटनगर उपखण्ड क्षेत्र के मैड कस्बे के खटीकों के मोहल्ले में पिछले 1० वर्षों से पेयजल संकट झेल रही महिलाओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। पानी की गंभीर समस्या से परेशान महिलाओं ने शुक्रवार को मटकी फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि उनके घरों में जलदाय विभाग के कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं आता, जबकि हर महीने नियमित रूप से पानी का बिल जरूर भेजा जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। गुस्साई महिलाओं ने बताया कि सरपंच के घर पहुंचकर समस्या से अवगत कराया गया तो सरपंच द्वारा ‘क्या आपने मुझे वोट दिया था’ कहे जाने बयान से महिलाओं में और अधिक रोष फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि रहते मोहल्ले में पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन बाद में जलदाय विभाग द्वारा उसे हटा दिया गया, जिससे स्थिति और



मोहल्ले के पुरुष और महिलाओं ने पानी की गंभीर समस्या से परेशान होकर प्रदर्शन किया।

भी गंभीर हो गई है। वर्तमान में मोहल्ले के लोग दूर-दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और जलदाय विभाग की उदासीनता पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए जल्द

समाधान की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चरमरा जाने के कारण ग्रामीणों को मजबूरी में निजी टैंकरो से पानी मंगवाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी जुटाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। मजबूरन जब से पैसे खर्च कर टैंकरो से पानी डलवाया जा रहा है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द

सीकर जिले में 2 1 4 5 1 6 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा

सीकर, (निर्स)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाये ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके।

■ गिवअप अभियान में 1046 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये, जिनसे वसूली की जायेगी

जिला रसद अधिकारी सीकर विजेन्द्र पाल ने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिवअप अभियान में सीकर जिले में 214516 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का

लाभ छोड़ा है। गिवअप अभियान में

सीकर जिले में 1०46 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जायेगी। गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित



मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



धनु

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।



मकर

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटकें हट्टे। कार्य बनने लगेगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक मामलों में उचित सोच-विचार हो सकता है।



कुंभ

व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



कन्या

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मीन

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

— दुर्धंत कुमार

— दुर्धंत कुमार

— दुर्धंत कुमार